



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 23 अप्रैल, 2007/3 वंशाख, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

कुल्लू, 30 मार्च, 2007

संख्या पी० सी० एच० (कु०) स्व०/2008-07-1622-25.-सदस्य सचिव एवं अधिशाषी अभियन्ता सिचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, कुल्लू-1 द्वारा विभाग के ध्यान में लाया गया है कि वर्ष 2005-06 में विकास खण्ड निरमण्ड की ग्राम पंचायत राहणू के लिए स्वजलधारा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए उनके कार्यालय पत्र संख्या आई० पी० एच०-आई० डी० के०-सी० बी०-स्व०/2006-16479-92, दिनांक 03-02-2006 के अन्तर्गत राशियां चैक द्वारा निर्मुक्त की गई है लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा निर्मुक्त राशि का उपयोग नहीं किया गया है और इस कारण हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार द्वारा आगामी किस्त प्राप्त

नहीं हो पा रही है क्योंकि भारत सरकार दूसरी किस्त तभी निर्मुक्त करती है जब प्रथम किस्त में जारी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उन्हें प्रेषित किया जाये।

क्रम सं०	योजना का नाम	अनुमानित लागत	भारत सरकार से प्राप्त भाग	प्रथम किस्त में निर्मुक्त राशि	चैक संख्या व दिनांक
01	पी० डब्ल्यू० एस० एस०-मोरीगाड से गांव धारटा बानीनाल आदि ग्राम पंचायत राहणू।	662400	629280	314640	950278 2-2-2006
02	पी० डब्ल्यू० एस० एस०-स्त्रोत पनैना से गांव मोवी, ठाराधार, ग्राम पंचायत राहणू	1052500	999900	499950	950845

उपरोक्त दोनों स्कीमों को एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर भी कार्य आरम्भ न करने के फलस्वरूप जिला पंचायत अधिकारी एवम् सचिव जिला परिषद्, कुल्लू के कार्यालय पत्र संख्या पी० सी० एच (कु०) स्व०/2006-5244, दिनांक 10 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रधान, श्रीमती उमा देवी, ग्राम पंचायत राहणू को उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निर्मुक्त राशि को एक सप्ताह के भीतर-2 जमा करने के निर्देश दिये गये थे लेकिन आज तक प्रधान द्वारा न तो राशि जमा करवाई गई और न ही कोई उत्तर सम्बन्धित कार्यालय को प्रेषित किया गया।

दिनांक 16-11-2006 को कार्यालय अध्यक्ष जिला परिषद् जो कि डी० डब्ल्यू० एस० एम० के अध्यक्ष भी है, के कार्यालय में जिला कुल्लू के उन सभी लाभान्वित समूहों जो स्वजलधारा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हो रहे हैं के प्रधान/सचिवों का एक दिवसीय सैमीनार/बैठक का आयोजन किया गया जिसमें प्रधान ग्राम पंचायत राहणू भी उपस्थित हुई थी। इस बैठक में भी सम्बन्धित प्रधान को अध्यक्ष जिला परिषद् तथा अन्य उपस्थित विभागीय अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से यह निर्देश दिए गए थे कि वे एक सप्ताह के भीतर-भीतर कार्य आरम्भ करवायें अन्यथा राशि विभाग को लौटाये परन्तु प्रधान द्वारा फिर भी कार्य आरम्भ नहीं करवाया गया।

दिनांक 23-12-2006 को प्रधान ग्राम पंचायत राहणू, उप-प्रधान, कनिष्ठ अभियन्ता तथा उप निरीक्षक विकास खण्ड निरमण्ड सहित अध्यक्ष जिला परिषद् व डी० डब्ल्यू० एस० एम० के कार्यालय में बुलाया गया। इस बैठक में प्रधान, उप-प्रधान, कनिष्ठ अभियन्ता, वाणीपुल, उपनिरीक्षक विकास खण्ड निरमण्ड के अतिरिक्त पंच श्री संगत राम, केसरी देवी, परमा राम (परमा नन्द) ज्वाली देवी तथा श्रीमती रोजनी देवी सदस्य, पंचायत समिति निरमण्ड भी उपस्थित हुए। बैठक में दोनों पक्षों को सुना गया। विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि एक योजना का कार्य प्रधान तथा दूसरी योजना का कार्य उप-प्रधान जो कि लाभान्वित समूह की कमेटी के प्रधान भी हैं, करेंगे लेकिन जब सहमति पत्र तैयार किया गया तो सम्बन्धित प्रधान सहमती पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व ही बैठक छोड़कर चली गई और जिला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा बार-बार दृष्टाप से सम्पर्क करने पर भी सम्बन्धित प्रधान कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई जबकि सांय 7 बजे तक कार्यालय में उनका सन्तजार किया गया।

उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती उमा देवी, प्रधान ग्राम पंचायत राहणू को जिला पंचायत अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय पंजीकृत ए० डी० पत्र संख्या पी०सी०एच०(कु०)स्व०/2006, दिनांक 8-1-2007 द्वारा राशि एक सप्ताह के भीतर-भीतर जमा करवाने के निर्देश दिये गये परन्तु प्रधान द्वारा न तो राशि स्वजलधारा खाते में जमा करवाई गई और न ही कोई उत्तर विभाग को प्रस्तुत किया :

दिनांक 6 जनवरी, 2007 को माननीय सांसद (मण्डी लोक सभा क्षेत्र) श्रीमती प्रतिभा सिंह जी की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में भी यह मामला लाया गया और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उपरोक्त योजनाओं की धनराशि सम्बन्धित पंचायत से वापिस लेकर स्वजलधारा खाते में जमा करवाई जाये व लाभान्वित समूह की गठित कमेटी से इन योजनाओं का निर्माण करवाया जाए। इसी के आधार पर पुनः पत्र संख्या 294 द्वारा सम्बन्धित प्रधान को राशि तीन दिनों के भीतर-भीतर जमा करवाने हेतु लिखा गया लेकिन बावजूद बार-बार लिखने के न तो प्रधान ने कोई उत्तर दिया और न ही राशि कार्यालय में जमा करवाई। इससे स्पष्ट है कि प्रधान द्वारा जानबूझ कर सरकारी आदेशों ककी अवहेलना की जा रही है।

इसके अतिरिक्त प्रधान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत श्री हीरा लाल, पंच को कार्य करने हेतु प्राधिकृत करने से भी यह स्पष्ट है कि सम्बन्धित प्रधान इन कार्यों को करने में असमर्थ है तथा विभाग को यह निर्देश देने की कोशिश कर रही है कि कार्य इनकी ही मर्जी से व उनके द्वारा चुने गये व्यक्ति से ही करवाया जाए जो कि स्पष्ट रूप से प्रधान पद का दुरुपयोग है।

माननीय अध्यक्ष जिला परिषद् जो कि स्वजलधारा मिशन के अध्यक्ष भी है के द्वारा स्वयं पंचायत के सनस्त पदाधिकारियों को बुला कर उपरोक्त कार्यों को व्यक्तिगत तौर पर सूचनाएं का पूरा प्रयास किया गया परन्तु प्रधान द्वारा इस प्रयास को भी विफल कर दिया गया। प्रधान न तो स्वयं कार्य कर रही है और न ही लाभान्वित समूह को कार्य करने दे रही है, और न ही राशि वापिस करना चाहती है। इस लाभान्वित जिला को भारत सरकार से स्वजलधारा योजना कि द्वितीय किशत प्राप्त होने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि जवतक नमस्त सम्बन्धित कार्यों की प्रथम किशत की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रेषित नहीं किये जाने, तब तक द्वितीय किशत की राशि जारी नहीं की जाएगी।

उपरोक्त प्रधान द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गयी है और जन हित में प्राप्त सरकारी धन को बिना किसी प्रयोजन के एक लम्बी अवधि (एक साल एक महीना और 14 दिन) तक रोक रखा है। इसी प्रकार प्रधान द्वारा अपने पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को रूकवाकर अपने पद का भी दुरुपयोग किया गया है।

पूर्व इसके कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत प्रधान ग्राम पंचायत राहगूं विकास खण्ड निरखंड के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाए, मैं चमेल सिंह, भा0 प्र0 से0, उपायुक्त, कुल्लू जिला कुल्लू, एतद्वारा प्रधान ग्राम पंचायत राहगूं को निर्देश देता हूं कि वह इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर-भीतर उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत करें। नियत अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें उक्त वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों अनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

चमेल सिंह (भा0 प्र0 से0),
उपायुक्त,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

4 अप्रैल, 2007

संख्या पी0 सी0 एस0 एम0 एल0 0—(4) 33/90-1282-86.—यह कि आपको बहसियन उप-प्रधान ग्राम पंचायत खटनोल, विकास खण्ड बसन्तपुर को जिला पंचायत अधिकारी, शिमला के आदेश संख्या पी0 सी0

एच0-एस0 एम0 एल0 (4) 33/90-3990-94, दिनांक 13-9-2006 के अन्तर्गत सरकारी धनराशि के दुरुपयोग/दुर्विनियोजन हेतु निलम्बित किया गया।

यह कि मामले की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत उपायुक्त, शिमला द्वारा जारी आदेश संख्या पी0सी0 एच-एस0 एम0 एल0 (4) 33/90-4405-4408, दिनांक 20-9-2006 अनुसार खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

यह कि उक्त आदेशों की अनुपालना में खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर द्वारा निर्धारित अवधि में जांच पूर्ण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है तथा उन द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के दृष्टिगत निम्न तथ्य समक्ष आए हैं :—

यह कि आपने वहैसियत उप-प्रधान निर्माण रास्ता शोधी से घाट का कार्य करवाया उस कार्य के लिए आप द्वारा तीन मजदूरों के जाली हस्ताक्षर कर 49 दिनों की फर्जी उपस्थिति दिखाई। जांच के दौरान मजदूरों के ध्यान अनुसार उन्हें 51 दिनों के मु0 70 रुपये प्रतिदिन की दर से 3,750 रुपये की अदायगी हुई जबकि आप द्वारा मु0 3,750 रुपये की बजाए मु0 7,000 रुपये का झूठा मस्ट्रोल दर्शाकर 3,430 रुपये की राशि का स्पष्ट दुरुपयोग किया है।

यह कि आप द्वारा स्वयं जांच के दौरान यह माना है कि निर्माण रास्ता शोधी से घाट का कार्य आप द्वारा ही करवाया है तथा मस्ट्रोल पर हाजरिया भी आप द्वारा ही लगाई गई है तथा हाजरियों में बढ़ोतरी भी आप द्वारा ही की गई है।

यह कि निर्माण रास्ता शोधी से घाट का निरीक्षण खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर द्वारा दिनांक 9-1-2007 को किया गया जांच के फलस्वरूप यह तथ्य समक्ष आया है कि उक्त रास्ते का निर्माण आप द्वारा घटिया स्तर का करवाया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत स्पष्ट है कि आप द्वारा उप-प्रधान जैसे गरिमा पूर्ण पद का दुरुपयोग किया और अपने पद के प्रभाव से पंचायत राशि का दुरुपयोग करके अपने कर्तव्यों को निभाने में असफल रहे हैं जिसके लिए आपके विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जानी आपेक्षित है।

अतः मैं, तरुण कपूर, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि उपरोक्त कृत्यों के लिए आपको उप-प्रधान पद से निष्कासित किया जाए। आपका उपरोक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर—2 खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को पहुंच जाना चाहिए, विहित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ कहना नहीं चाहते तथा नियमानुसार एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

तरुण कपूर
उपायुक्त, शिमला,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0)

आदेश

शिमला-2, 3 अप्रैल, 2007

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (4) 26/2006-1246-51.—यह कि विकास खण्ड रामपुर से, प्राप्त विशेष रिपोर्ट के दृष्टिगत श्री हरि ओम ठाकुर को अधोहस्ताक्षरी द्वारा आदेश संख्या पी0 सी0 एच0-

एस0 एम0 एल (4) 26/2006-5784-88, दिनांक 9-10-2006 के अन्तर्गत निम्न आरोप के लिए निलम्बनाथ कारण बताओ नोटिस दिया गया था।

1. यह कि श्री हरि ओम ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत गोपालपुर, प्रायः ग्राम सभा क्षेत्र से बाहर रहते हैं जिससे पंचायत के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं।

2. यह कि ग्राम पंचायत की रोकड़ वही, कार्यवाही पुस्तिका तथा बैंक पास बुकें आदि अपूर्ण हैं।

3. यह कि प्रधान ग्राम पंचायत ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक रामपुर बुधौहर से एकाउन्ट नं० 3806 शीर्ष एस0 जी0 आर0 वाई0 से दिनांक 1-7-2006 को मु० 50,000/- रुपये आहरण करके अपने पास रखे हैं राशि कहीं खर्च नहीं की गई है। इस प्रकार प्रधान द्वारा मु० 50,000/- रुपये सरकारी धन का छल हरण किया गया है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर श्री हरि ओम ठाकुर प्रधान द्वारा दिनांक 16 अक्तूबर, 2006 को दिया गया श्री हरि ओम ठाकुर प्रधान द्वारा कारण बताओ नोटिस पर दिया गया उत्तर अस्पष्ट व असन्तोषजनक होने के फलस्वरूप उन्हें अधोहस्ताक्षरी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिनांक 30-11-2006 को दिया गया। सुनवाई उपरान्त श्री हरि ओम ठाकुर, प्रधान को स्वीकृत कार्यों को तुरन्त आरम्भ करने व एक मास के भीतर-भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिये तथा उन द्वारा अधोहस्ताक्षरी को कार्य पूर्ण करने बारे आश्वस्त किया गया।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी रामपुर ने अपने पत्र पृष्ठांकन संख्या 5488, दिनांक 22-3-2007 द्वारा सूचित किया है कि पंचायत में कोई भी विकासार्थक कार्य आरम्भ नहीं हुए हैं कार्यों का धीरा निम्न प्रकार से है :—

क्र० सं०	ग्राम पंचायत का नाम	स्कीम का नाम व शीर्ष	स्वीकृति की दिनांक	कितनी जारी की गई	आवंटित की गई राशि	शेष
1	2	3	4	5	6	7
1.	गोपालपुर	एम0 एम0 भवन पटो बसेरा एन0 सी0	29-04-2005	1,00,000/- रु०	51,000/- रु०	49,000/- रु०
2.	गोपालपुर	रास्ता करटोट खड से गांव करटोट तक एम0 जी0 आर0 वाई0	10-10-2006	50,000/- रु०	18,040/- रु०	31,960/- रु०
3.	गोपालपुर	रास्ता बसेरा से बुरी एस0 जी0 आर0 वाई0	2-9-2006	15,000/- रु०	5,414/- रु०	9,586/- रु०
4.	गोपालपुर	एम0 एम0 भवन गांव रतनपुर वी0 के0 वी0 एन0 वाई0	18-10-2005	1,00,000/- रु०	—	1,00,000/- रु०

1	2	3	4	5	6	7
5.	गोपालपुर	श्रीन वैली वाई 0 एम 0 भवन गोपालपुर वा 0 के 0 बी 0 एन 0 वाई 0	19-6-2006	1,00,000/- रु 0	--	1,00,000/- रु 0
6.	गोपालपुर	कमनीयूटी भवन कर- टोट एम 0 पी 0 एल 0 ए 0 डी 0	2-11-2005	75,000/- रु 0	--	75,000/- रु 0
7.	गोपालपुर	रास्ता कुहल से करटोट एम 0 पी 0 एल 0 ए 0 डी 0	2-11-2005	15,000/- रु 0	--	15,000/- रु 0
8.	गोपालपुर	एम 0 एम भवन रतन- पुर एस 0 जे 0 बी 0 एन 0 एल 0	24-10-2005	1,00,000/- रु 0	--	1,00,000/- रु 0
9.	गोपालपुर	जी 0 एम 0 एस 0 करटोट ओ 0 बी 0 बी 0	26-3-2003	2,00,000/- रु 0	19,200/- रु 0	8,000/- रु 0
10.	गोपालपुर	गांव बसेरा में एक कमरा एम 0 पी 0 एल 0 ए 0 डी 0	14-2-2007	1,00,000/- रु 0	--	1,00,000/- रु 0

उपरोक्त के दृष्टिगत स्पष्ट है कि श्री हरि ओम ठाकुर प्रधान ग्राम पंचायत गोपालपुर द्वारा प्रधान जैसे गरिमा पद पर कार्यरत रहते हुए खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर व ग्रोहस्ताक्षरी द्वारा व्यक्तिगत निर्देश देने के बावजूद भी कार्य आरम्भ न करके जहां पंचायत राशि का दुरुपयोग किया गया है वहां वह अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में भी असफल रहे हैं जिसके कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और विकास कार्यों को आरम्भ न करने से आम जनता को राशि स्वीकृत होने के फलस्वरूप भी उसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

अतः मैं, जोगिन्द्र कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, शिमला उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो कि मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2) में विहित है का प्रयोग करते हुए श्री हरि ओम ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत गोपालपुर, विकास खण्ड रामपुर जिला शिमला को उनके पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश प्रदान करता हूं तथा यह भी आदेश देता हूं कि वह अपना समस्त कार्यभार उप-प्रधान, ग्राम पंचायत गोपालपुर, विकास खण्ड रामपुर को तुरन्त सौंप दे।

कारण बताओ नोटिस

शिमला, 5 अप्रैल, 2007

संख्या पी 0 सी 0 एच 0 एस 0 एम 0 एल 0 (4) 97/77-2063-67.--यह कि उप-महानिरीक्षक पुलिस राज्य सतकर्ता एवं अष्टाचार रोधी ब्यूरो के माध्यम से व श्री भाग सिंह पुत्र श्री तुना राम, गांव गड्ढी,

द्वारा सदस्य ग्राम पंचायत हिमरी के विरुद्ध गांव के भरण-पोषण, निर्माण स्टोरेज टैंक डिबर नाला के लिए क्रय किए गए सीमेंट, सरिया व रेत को अपने घर ले जाकर सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करने तथा उक्त कार्यों पर लगे मजदूरों को उन द्वारा निष्पादित कार्य से कम मजदूरी व मजदूरों जिन्होंने कमी भी मौका पर कार्य नहीं किया है को राशि की अदायगी दिखाकर पंचायत धनराशि के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायत प्राप्त हुई है।

यह कि उक्त शिकायत पर प्रारम्भिक छानबीन खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर द्वारा करवाई गई, खण्ड विकास अधिकारी बसन्तपुर द्वारा दिनांक 27-12-2006 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से निम्न तथ्य समक्ष आए हैं :-

क्रम संख्या	मजदूर का नाम	शिकायत में दर्शाए गए दिन	मस्ट्रोल में दिखाए गए दिन	जितने दिनों की अदायगी की	मजदूर ने जो राशि प्राप्त की	वास्तविक राशि जो दी जानी है	शेष राशि अदायगी हेतु	अधिक की गई अदायगी
1.	श्री प्रेम लाल	30	26	23	1840	2100	260	—
2.	श्री खुबी राम	34	29	29	2030	2380	350	—
3.	श्री थोला राम	32	12	—	—	2240	2240	—
4.	श्री लेख राम	21	25	25	1750	1470	—	280
5.	श्री हितेन्द्र	25	29	29	2030	1750	—	280
6.	श्री पूर्ण दास	21	29	29	2552	1848	—	704
7.	श्री कुलदीप	—	25	25	1750	—	—	1750

उपरोक्त विवरण के अतिरिक्त छानबीन रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि एक मजदूर श्री हितेन्द्र को दुलाई सीमेंट व रेत के मु0 180 रुपये देने अभी शेष हैं। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 24-4-2006 के अनुसार श्री टेक चन्द, वार्ड सदस्य को इस कार्य का मस्ट्रोल जारी किया गया।

यह कि छानबीन रिपोर्ट से स्पष्ट है कि श्री टेक चन्द, सदस्य, ग्राम पंचायत हिमरी द्वारा निर्माण कार्य स्टोरेज टैंक डीबर नाला मस्ट्रोल कार्य पर लगे मजदूरों द्वारा तैयार नहीं किया गया तथा उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए क्रम संख्या 1, 2 व 3 मजदूरों को कम मजदूरी देकर व क्रम संख्या 4, 5, 6 व 7 पर अंकित मजदूरों को अधिक मजदूरी देकर मु0 6,044 रुपये का दुरुपयोग किया।

अतः मैं, जोगिन्द्र कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, शिमला उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो कि मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2) (2-ए0) में निहित हैं, का प्रयोग करते हुए श्री टेक चन्द, सदस्य, ग्राम पंचायत हिमरी, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी को पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जोगिन्द्र कुमार शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित